स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड: ₹945 करोड़ की मंज़ूरी

स्टार्टअप / वित्त / संघवाद | समाचार संदर्भ: स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना पर लोक सभा उत्तर, 21 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

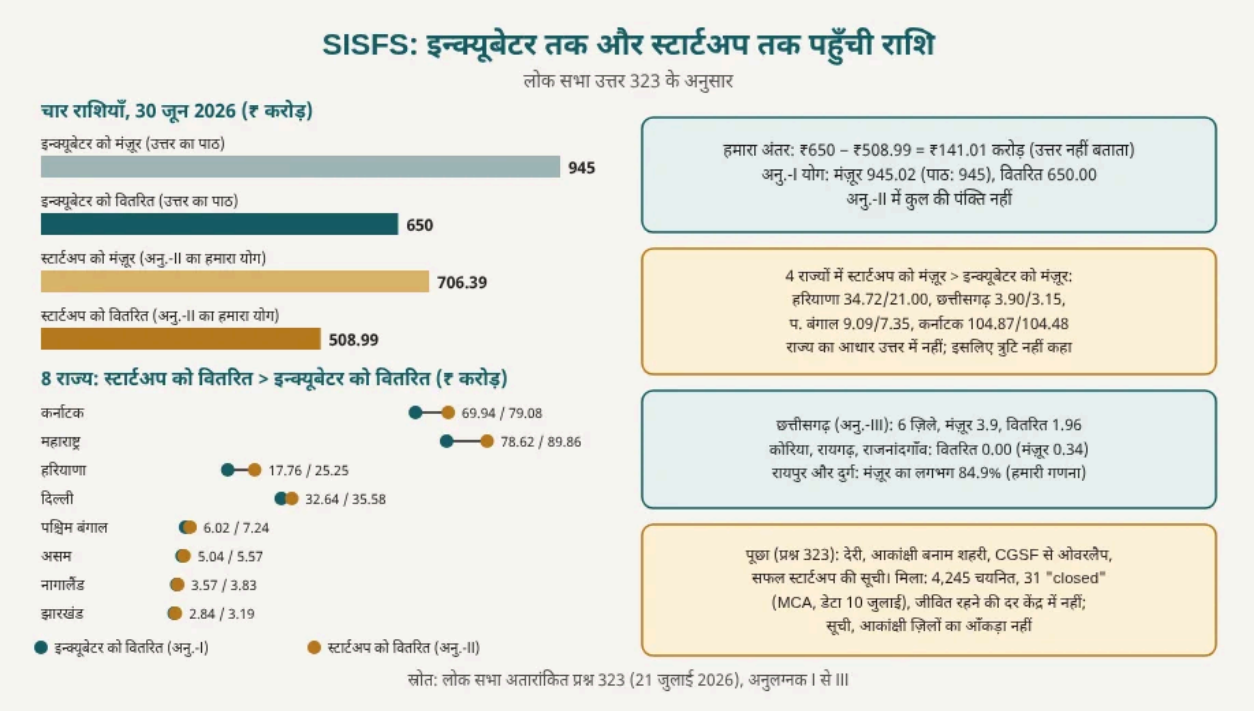
स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना (SISFS) उत्तर के अनुसार शुरुआती चरण के पात्र स्टार्टअप को इन्क्यूबेटरों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू हुई। इसमें चयनित इन्क्यूबेटर स्टार्टअप को माइलस्टोन-आधारित किस्तों में धन जारी करते हैं; उत्तर के अनुसार पात्र स्टार्टअप को प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या उत्पाद-परीक्षण के लिए ₹20 लाख तक अनुदान और बाज़ार-प्रवेश, व्यावसायीकरण या विस्तार के लिए ₹50 लाख तक निवेश (परिवर्तनीय डिबेंचर, ऋण या ऋण-संबद्ध साधनों से) मिल सकता है।

खबरों में क्यों

21 जुलाई 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने श्री बृजमोहन अग्रवाल के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 323 का उत्तर दिया। प्रश्न में जून 2026 तक आवंटित और उपयोग की गई निधि और चालू इन्क्यूबेटर, इन्क्यूबेटर-माध्यम वाली वितरण-व्यवस्था में देरी की जानकारी, आकांक्षी ज़िलों और शहरी केंद्रों के बीच अंतर और छत्तीसगढ़ की अपनी सीड फ़ंड सहायता से ओवरलैप (राज्य-वार और छत्तीसगढ़ के ज़िला-वार), सुधारात्मक कदम और योजना से निकले सफल स्टार्टअप की सूची पूछी गई थी। उत्तर के साथ तीन अनुलग्नक हैं।

मुख्य अवधारणा: इन्क्यूबेटर तक और स्टार्टअप तक पहुँची राशि अलग हैं

उत्तर के अनुसार 30 जून 2026 तक 219 चालू इन्क्यूबेटर चुने गए, जिनके लिए कुल ₹945 करोड़ की निधि मंज़ूर है और ₹650 करोड़ इन्क्यूबेटरों को वितरित हो चुके हैं। अनुलग्नक-II में उसी तारीख़ की “स्टार्टअप को चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा” मंज़ूर और वितरित राशि अलग दी गई है। यानी चार अलग गिनतियाँ हैं: इन्क्यूबेटर को मंज़ूर, इन्क्यूबेटर को वितरित, स्टार्टअप को मंज़ूर, स्टार्टअप को वितरित।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

राष्ट्रीय आँकड़े, 30 जून 2026 (उत्तर का पाठ)	**219 चालू इन्क्यूबेटर; कुल मंज़ूर निधि ₹945 करोड़; इन्क्यूबेटरों को वितरित ₹650 करोड़।**
स्टार्टअप (उत्तर का पाठ)	30 जून 2026 तक सहायता के लिए चयनित स्टार्टअप 4,245; इनमें से MCA के आँकड़ों (डेटा 10 जुलाई 2026 को साझा) के अनुसार “closed (dissolved/struck-off)” वर्ग में 31।
अनुलग्नक-I (27 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पंक्तियाँ)	इन्क्यूबेटरों को मंज़ूर राशि सबसे अधिक: महाराष्ट्र ₹120.75 करोड़, कर्नाटक 104.48, तमिलनाडु 96.34, गुजरात 81.38, तेलंगाना 71.35। छत्तीसगढ़: मंज़ूर 3.15, वितरित 2.78।
अनुलग्नक-II (32 पंक्तियाँ)	स्टार्टअप को मंज़ूर सबसे अधिक: महाराष्ट्र ₹117.32 करोड़, कर्नाटक 104.87, तमिलनाडु 69.16, गुजरात 51.69, दिल्ली 50.58। छत्तीसगढ़: मंज़ूर 3.90, वितरित 1.96।
अनुलग्नक-III: छत्तीसगढ़, ज़िला-वार (स्टार्टअप को)	रायपुर 1.69 मंज़ूर, 0.95 वितरित; दुर्ग 1.62 और 0.92; बिलासपुर 0.25 और 0.09; कोरिया 0.12 और 0.00; रायगढ़ 0.16 और 0.00; राजनांदगाँव 0.06 और 0.00; कुल 3.9 और 1.96।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो अनसुलझा है

जो मेल खाता है (हमारी गणना): अनुलग्नक-I की 27 पंक्तियों का योग वितरित में ठीक ₹650.00 करोड़ है, जो उत्तर के पाठ से मिलता है; मंज़ूर का योग ₹945.02 करोड़ है, जबकि पाठ में ₹945 करोड़ है (0.02 का अंतर)। अनुलग्नक-III के छह ज़िलों का योग अनुलग्नक-II में छत्तीसगढ़ की पंक्ति (3.90 और 1.96) से मिलता है। अनुलग्नक-II में कुल की पंक्ति नहीं है; हमारा योग मंज़ूर ₹706.39 करोड़ और वितरित ₹508.99 करोड़ है।

हमारी गणना: अंतर: अनुलग्नकों के योग से इन्क्यूबेटरों को वितरित ₹650 करोड़ और स्टार्टअप को वितरित ₹508.99 करोड़ का अंतर ₹141.01 करोड़ है (स्टार्टअप को वितरित राशि इन्क्यूबेटरों को वितरित का लगभग 78.3%)। स्टार्टअप को मंज़ूर ₹706.39

करोड़ इन्क्यूबेटरों को मंज़ूर ₹945.02 करोड़ का लगभग 74.7% है। उत्तर इस अंतर को स्पष्ट नहीं करता।

जो अनसुलझा है: राज्य-वार उलटाव: चार राज्यों में स्टार्टअप को मंज़ूर राशि इन्क्यूबेटरों को मंज़ूर राशि से अधिक है: हरियाणा 34.72 बनाम 21.00, छत्तीसगढ़ 3.90 बनाम 3.15, पश्चिम बंगाल 9.09 बनाम 7.35, कर्नाटक 104.87 बनाम 104.48 (₹ करोड़)। आठ राज्यों में स्टार्टअप को वितरित राशि इन्क्यूबेटरों को वितरित से अधिक है: कर्नाटक 79.08 बनाम 69.94, महाराष्ट्र 89.86 बनाम 78.62, हरियाणा 25.25 बनाम 17.76, दिल्ली 35.58 बनाम 32.64, पश्चिम बंगाल 7.24 बनाम 6.02, असम 5.57 बनाम 5.04, नागालैंड 3.83 बनाम 3.57, झारखंड 3.19 बनाम 2.84। उत्तर नहीं बताता कि दोनों अनुलग्नकों में राज्य किस आधार पर तय हुआ है, इसलिए हमने इन्हें त्रुटि नहीं कहा।

जो तुलनीय नहीं: अनुलग्नक-II में पाँच प्रविष्टियाँ (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय) हैं जो अनुलग्नक-I में नहीं हैं। 4,245 स्टार्टअप (30 जून तक) और 31 बंद (MCA डेटा 10 जुलाई को साझा) अलग तारीख़ों के हैं, इसलिए हमने इनका प्रतिशत नहीं निकाला; उत्तर के अनुसार स्टार्टअप की जीवित रहने की दर केंद्र में नहीं रखी जाती।

महत्व: क्षेत्रीय संतुलन और वितरण की गति

छत्तीसगढ़ का ब्योरा (हमारी गणना): छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को मंज़ूर ₹3.90 करोड़ में से ₹1.96 करोड़ (लगभग 50.3%) वितरित है। रायपुर और दुर्ग में मंज़ूर राशि का लगभग 84.9% (3.31 करोड़) और वितरित का लगभग 95.4% (1.87 करोड़) है। कोरिया, रायगढ़ और राजनांदगाँव में 0.34 करोड़ मंज़ूर हैं और वितरित 0.00 है। उत्तर इसका कारण नहीं देता।

राज्यों के बीच संकेंद्रण (हमारी गणना): इन्क्यूबेटरों को मंज़ूर राशि की पाँच सबसे बड़ी प्रविष्टियाँ (महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना) ₹945.02 करोड़ का लगभग 50.2% हैं। स्टार्टअप को मंज़ूर राशि में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का हिस्सा ₹706.39 करोड़ का लगभग 41.2% है।

स्टार्टअप तक पहुँच की गति: राज्य-वार स्टार्टअप को वितरित बनाम मंज़ूर अनुपात मणिपुर में लगभग 27.3% और पंजाब में लगभग 44.7% से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा अरुणाचल प्रदेश में 100% तक है; उत्तर इन अंतरों के कारण नहीं देता।

चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है

पूछा गया, पर नहीं मिला: प्रश्न (ख) में वितरण-देरी की जानकारी पूछी गई थी; उत्तर देरी की स्वीकृति या ऐसा कोई आँकड़ा नहीं देता, केवल यह बताता है कि माइलस्टोन-आधारित किस्तें, समितियाँ (EAC, ISMC), समीक्षा बैठकें, सलाह और प्रशिक्षण हैं और योजना को "हाल ही में" विस्तार मिला है (तारीख़ नहीं दी गई)। प्रश्न (ग): आकांक्षी ज़िलों बनाम शहरी केंद्रों का उपयोग-अंतर नहीं दिया गया; केवल राज्य-वार और छत्तीसगढ़ के ज़िला-वार आँकड़े हैं, और छत्तीसगढ़ की सीड फ़ंड सहायता (CGSF) के साथ ओवरलैप का कोई आँकड़ा नहीं, केवल दोनों योजनाओं की पात्रता का ब्योरा (SISFS में अन्य सरकारी योजना से ₹10 लाख से अधिक सहायता न मिली हो; CGSF में ₹10 लाख तक MVP सहायता)। प्रश्न (ङ): "सफल स्टार्टअप" की सूची नहीं; केवल चयनित और बंद की संख्या।

अनसुलझे बिंदु: अनुलग्नक-I और II के राज्य-वार उलटाव; ₹141.01 करोड़ का अंतर; चालू इन्क्यूबेटरों की राज्य-वार संख्या (कोई कॉलम नहीं); "extension" की अवधि; आकांक्षी ज़िलों का हिस्सा।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा अतारांकित प्रश्न 323 का आधिकारिक PDF (उत्तर और तीनों अनुलग्नक) पूरा पढ़ा। SISFS दिशा-निर्देश, SISFS पोर्टल, MCA डेटा और छत्तीसगढ़ की नीति को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा गया।

आगे की राह

इसे 21 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; राज्य-वार उलटाव, इन्क्यूबेटर के पास पड़ी राशि और आकांक्षी ज़िलों की स्थिति के लिए SISFS पोर्टल के आँकड़े या आगे के आधिकारिक उत्तर देखने होंगे।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) इन्क्यूबेटर को मंज़ूर/वितरित और स्टार्टअप को मंज़ूर/वितरित राशि; (2) चयनित स्टार्टअप और बंद या सफल स्टार्टअप; (3) योजना की पात्रता-सीमाएँ और राज्य की योजना की सीमाएँ; (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-III: निवेश, उद्यमिता और स्टार्टअप; GS-II: केंद्र-राज्य संबंध और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

स्टार्टअप इंडिया सीड फ़ंड योजना के सरकारी आँकड़ों से इन्क्यूबेटर-माध्यम वाली वितरण-व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं? क्षेत्रीय संतुलन और वितरण की गति जाँचने के लिए किन अतिरिक्त आँकड़ों की ज़रूरत होगी?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: SISFS, इन्क्यूबेटर-माध्यम मॉडल और प्रश्न 323।

मुख्य भाग में: राष्ट्रीय आँकड़े (219 इन्क्यूबेटर, ₹945 करोड़ मंज़ूर, ₹650 करोड़ वितरित, 4,245 स्टार्टअप, 31 बंद, उत्तर के आँकड़े); चार अलग राशियाँ और हमारा अंतर ₹141.01 करोड़; राज्य-वार उलटाव और असंगति का अनसुलझा रहना; छत्तीसगढ़ का उदाहरण (ज़िला-वार, SISFS बनाम CGSF की पात्रता); उत्तर में क्या नहीं (आकांक्षी ज़िले, देरी, सफल स्टार्टअप की सूची); आवश्यक आँकड़े।

निष्कर्ष में: इन्क्यूबेटर को मंज़ूरी और स्टार्टअप तक वितरण को अलग रखते हुए क्षेत्रीय पहुँच परखें; वितरण की गति और संतुलन का निष्कर्ष तभी दें जब राशियों के अंतर, समय और ज़िला-वार पहुँच का ब्योरा स्पष्ट हो।

स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 323 और उत्तर, 21.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक-I से III सहित)

स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 323 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक-I से III पूरे पढ़े गए। SISFS दिशा-निर्देश, पोर्टल और MCA डेटा नहीं पढ़े गए।

याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार SISFS में 30 जून 2026 तक ₹945 करोड़ मंज़ूर और ₹650 करोड़ इन्क्यूबेटरों को वितरित हैं, जबकि अनुलग्नकों के हमारे योग से स्टार्टअप को वितरित ₹508.99 करोड़ है; चार राज्यों में स्टार्टअप को मंज़ूर राशि इन्क्यूबेटरों को मंज़ूर से अधिक है, और देरी, आकांक्षी ज़िलों और सफल स्टार्टअप की सूची उत्तर में नहीं है।